Nandani Creation Limited

Jaipur Kurti .Com | AMAIVA BY JAIPUR KURTI | Desi Fusion

SYMBOL: NANDANI
ISIN: INE696V01013

Dated: 20.07.2020

To,
The Manager-Listing Department,
The National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, NSE Building,
Bandra Kurla Complex,
Bandra East,
Mumbai-400 051
Fax: 022-26598237, 022-26598238

Subject: Disclosure under Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Respected Sir,

With respect to the captioned subject, we feel great pleasure to inform you that the interview of our **Chairman & Managing Director- "Mr. Anuj Mundhra"** was published in ***"Nafa Nuksan"* Newspaper** on ***Saturday, 18th Day of July, 2020*** briefly specifying the following:

- Current/Present Impact of Coronavirus on the Corporates
- Benefits of Financial Assistance provided by Govt. of India/RBI on Lower Rate of Interest to the Corporates
- Advisory Suggestions on the waiver of Interest on account of the Moratorium opted by the Corporates
- Future Impact of Coronavirus on the Corporates etc.

We are herewith attaching the copy of the Newspaper Clipping for your records.
Kindly take the above intimation on your record and inform all those concerned.

Yours faithfully
For NANDANI CREATION LIMITED

Nandani Creation Limited JAIPUR

GUNJAN JAIN
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Encl: Clippings of Newspapers

CIN No.: L18101RJ2012PLC037976
G-13, AARNA-3, Kartarpura Industrial Area, Bais Godown, Jaipur -302 006 Rajasthan INDIA
+91-141-4037596
+91-141-4029596
info@jaipurkurti.com
www.jaipurkurti.com
RAJASTHAN | MAHARASHTRA | KARNATAKA | HARYANA | WEST BENGAL

आर.एन.आई. नं.: 63696/96 | www.nafanuksan.com | शनिवार, 18 जुलाई, 2020 | वर्ष 25 अंक 61 | मूल्य: ₹ 6.00 | पेज: 8

नफा नुकसान

जो पढ़े... आगे बढ़े...

Socio-Economic Daily

राज्यस्तरीय व्यापारिक दैनिक

जयपुर (डाक संस्करण)

जियो में होल्डिंग बेचने से प्राप्त फंड्स को कहां इंवेस्ट कर रही है रिलायंस?

कॉर्पोरेट संवाददाता

जयपुर। मुकेश अंबानी प्रमोटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. ने जियो में बेची गई होल्डिंग व राइट्स इश्यू के जरिए प्राप्त हुए करीब 35,000 करोड़ रुपये का निवेश देश के डेब्ट फंड्स में किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह फंड्स अल्ट्रा-शॉर्ट व मनी-मार्केट फंड्स के साथ ही 3-5 वर्ष की मेच्योरिटी वाले अन्य डेब्ट फोकस्ड फंड्स में डाले गए हैं। फॉरेन करेंसी डीलर्स का भी कहना है कि पिछले कुछ सप्ताह से रिलायंस-रिलेटेड फंड्स देश में आ रहा है व संभवतया इसी कारण पिछले महिने डॉलर के मुकाबले रुपया 1 प्रतिशत से भी अधिक मजबूत हुआ है। सूत्रों के अनुसार रिलायंस द्वारा डेब्ट फंड्स में जो इंवेस्टमेंट किया गया है वह लांग-टर्म के लिए है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि रिलायंस इंटरेस्ट-रेट्स साइकिल पर दांव लगा रही है। आरबीआई द्वारा इंटरेस्ट रेट्स में और कमी किए जाने की संभावना के चलते शॉर्ट-ड्यूरेशन बांड्स में तेजी देखने को मिल रही है।

स्टॉक मार्केट्स में तेजी जारी

सेंसेक्स 37000 पार

मुंबई/एजेंसी। बीएसई सेंसेक्स शुक्रवार को 548 अंक उछलकर 37,000 अंक के स्तर को लांघकर 37,020.14 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में अच्छी हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआई बैंक और एचयूल में अच्छी तेजी के साथ बाजार में यह उछाल दर्ज किया गया। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरू से ही बढ़त में रहा और अंत में 548.46 अंक यानी 1.50 प्रतिशत की जोरदार तेजी के साथ 37,020.14 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 161.75 यानी 1.51 प्रतिशत उछलकर 10,901.70 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक लाभ में ओएनजीसी रही। इसमें 5.52 प्रतिशत की तेजी आयी। उसके बाद टाइटन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस का स्थान रहा। दूसरी तरफ टीसीएस, नेस्ले इंडिया, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और एक्सिस बैंक में गिरावट दर्ज की गयी। कारोबारियों के अनुसार वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के साथ सूचकांक में अच्छी हिस्सेदारी रखने वाले शेयर केंद्रित लिवाली से बाजार में मजबूती आयी। चीन का शंघाई, हांगकांग और दक्षिण कोरिया का सोल लाभ में रहे जबकि जापान का टोक्यो बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोप में शुरुआती कारोबार में जर्मनी और ब्रिटेन के बाजारों में तेजी रही जबकि फ्रांस में गिरावट दर्ज की गयी।

बीएसई पर सर्वाधिक बढ़ने वाले ए समूह के शेयर

Security Name	LTP	% Chg
HEG	831.25	14.43
IDEA	8.88	12.83
BPCL	443.9	12.65
HAL	937.5	11.56
HATHWAY	43.6	9.96
ORIENTCEM	69.8	9.49
BDL	392.35	9.12
DCAL*	172.9	8.03
HIMATSEIDE	61	7.68
CHENNPETRO	82.65	7.48

what next?

कोरोनावायरस का देश में प्रवेश हुए कई महीने हो गये हैं और बीमारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लंबे लॉक डाउन का परिदृश्य है, तो औद्योगिक-कारोबारी गतिविधियां शुरू होने लगी हैं, पर अब क्या होगा, यह सवाल सभी के पास है और इस सवाल पर राजस्थान का कारोबारी तबका क्या कहता है यह हम यहां अवगत करा रहे हैं :

'ब्याज पर ब्याज वसूल न किया जाये'

नंदिनी क्रियेशंस के अनुज मूंदड़ा कहते हैं कि सरकार ने उधार चुकाने की अवधि तो बढ़ा दी है, लेकिन इस बढ़ी हुई अवधि में जो ब्याज चुकाया जाना था, उस बकाया ब्याज पर भी बैंक ब्याज वसूल कर रहे हैं, यह उद्योग-व्यापार जगत के साथ कुठाराघात है। सरकार की तरफ से बैंकों को निर्देश देना चाहिये कि वे कम से कम ब्याज पर तो ब्याज वसूल न करें। इससे तो कारोबार की लागत बढ़ रही है और वह भी इस मंदी और कोरोना के दौर में। उनका कहना था इसके उलट यह होना चाहिये कि जो मोरेटोरियम अवधि बढ़ाई गई है, उसे छह माह की बजाय एक वर्ष किया जाये, ताकि कारोबारी को राहत मिल सके। एक वर्ष तक यदि ब्याज न दिये जाने की छूट मिले तो जो नुकसान कारोबारी को हुआ है, उसे रिकवर करने का मौका भी मिल जायेगा और कारोबारी स्थितियां भी बेहतर हो सकेगी। पर अभी तो कारोबारी की चिंता यही है कि मोरेटोरियम अवधि में देय ब्याज पर ब्याज कैसे चुकाये। इस तरह सरकार ने कारोबारी तबके पर दोहरा बोझ डाल दिया है।

असर कब तक : कोरोना वायरस का असर कब तक रहेगा, इस बारे में उनका कहना था कि जिस गति से यह फैल रहा है और देश में संक्रमितों की दैनिक संख्या 30-32 हजार के करीब आ गई है, तो यह स्थिति चिंताजनक है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को ही सोचना चाहिये कि ऐसे में क्या करें। सबसे बड़ी बात तो सख्ती की है, सरकार सख्ती करे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि जून माह के दूसरे सप्ताह से लाक डाउन में शिथिलता दी गई थी, उसके बाद से मरीजों-संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार के लिए ऐहतियाती कदम उठाना जरूरी हो गया है।

बाजार स्थिति : इस समय बाजार दो तरह से चल रहा है एक फिजिकल और दूसरा आन लाइन। फिजिकल बाजार में ग्राहकों का अभाव है और लोग बहुत कम आ रहे हैं। वैसे भी जुलाई-सितंबर के बीच कारोबार ठंडा रहता है, उसके पहले जून तक लाक डाउन के कारण कारोबारी स्थितियां बेहतर नहीं थी। अब आन लाइन काम अधिक चल रहा है, कई तरह के उत्पादों में इस काम का अच्छा परिदृश्य बना हुआ है। खरीद-फरोख्त भी ठीक है और मांग भी। लोग बाजार जा कर शो रूमों में अपनी पसंद से खरीदने की बजाय आन लाइन पसंद कर उत्पाद खरीदने में अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं।

आगे क्या लगता है : कहते हैं कि अभी छह माह आन लाइन बाजार ही अधिक चलेगा। भौतिक कारोबार में अभी सुधार के लिए समय है। हां जनवरी से उठाव शुरू हो जायेगा यह माना जा रहा है।

20 लाख करोड़ का पैकेज : कहते हैं कि कारोबारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। हम लोगों ने बैंकों से उधार ले रखा था तो अतिरिक्त कार्यशील पूंजी 8.00-8.50 प्रतिशत ब्याज पर हमें मिल रही है। इतना ही नहीं सिडबी की एक योजना के तहत तो 5.00-5.50 प्रतिशत ब्याज पर ही उधार मिल रहा है। इस तरह कारोबारी सरकार की ओर से जारी योजनाओ को देखे, समझे तो फायदा मिल सकता है।

सरकार से अपेक्षा : एन बी एफ सी से कई बार उधार लेना पड़ जाता है। उनके लिए भी वही प्रावधान लागू किये जायें जो बैंकों के लिए हों, इससे कारोबारी को सहूलियत रहेगी और उनके यहां भी बिजनस का फ्लो बढ़ेगा। सरकार उन्हें फंडिंग के जरिये सहायता दे रही है, लेकिन उनसे संबंधित कायदे-कानूनों का सरलीकरण तो करे।

'इकोनोमिक्स का प्रेक्टिकल ज्ञान'

जितेन्द्र कोठारी

स्कूल व कॉलेजों में इकॉनोमिक्स एक संपूर्ण सब्जेक्ट है जिसमें कई थ्योरियां है और प्रेक्टिकल घटनाक्रमों के आधार पर इसके नियम स्टूडेंट को समझाए जाते रहे हैं। इकोनॉमिक्स के नियम मुख्यत: प्राइस सिग्नल, जॉब, सरकारों का रोल, डिमांड, सप्लाई, टैरिफ, प्रॉडक्टिविटी जैसे आधारों पर बेस्ड होते हैं जिनसे इकॉनोमी व कारोबारों पर संभावित प्रभावों को मॉनीटर किया जा सकता है। इन आधारों को ध्यान में रखकर ही कारोबारियों व सरकारों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं जो उनकी रेगुलर लाइफ का प्रमुख हिस्सा है। कोरोना संकट के समय में इकोनॉमिक्स को समझने के लिए किताबी नॉलेज की जगह प्रेक्टिकल नॉलेज जरूरी है जो हमारे चारों ओर मौजूद है क्योंकि बदले हुए कारोबारी माहौल में हर कोई इकॉनोमिक्स के आधारों की बारीकी से स्टडी करने लगा है व इनके प्रभावों का असर भी साक्षात रूप में अपने कारोबारों या देश की इकॉनोमी पर दिखाई दे रहा है

इनमें से कई आधार पुरानी मान्यताओं से उल्टा व्यवहार करते हुए यह सिग्नल दे रहे हैं कि इनके मूवमेंट का कोई तय फार्मूला नहीं है। उदाहरण के लिए तेल की कीमतों में गिरावट ने इसे इतिहास के न्यूनतम लेवल पर ला दिया पर सरकारी दखल की वजह से इसकी कीमतें कम नहीं हुई जो इकॉनोमिक्स के नियम के विरुद्ध है। दूसरी तरफ कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी प्रॉडक्ट जैसे हैंड सेनेटाईजर, फेस मास्क, पीपीई किट की शुरुआती दिनों में शॉर्टेज होने से लोगों ने ज्यादा कीमत देकर भी इनकी खरीददारी की व इनसे संबंधित कारोबारियों ने बड़ा मुनाफा भी कमाया जो इकॉनोमिक्स के सिद्धांत के अनुरूप ही था जिसमें सप्लाई कम होने पर कीमतें बढ़ जाती है। इन दोनों प्रेक्टिकल उदाहरणों से यह समझा जा सकता है कि इकॉनोमिक्स के तय नियम हर तरह के प्रॉडक्ट पर एक तरह से काम नहीं करते बल्कि इनको अपने-अपने फायदे व स्वार्थ के लिए बदला भी जा सकता है।

इकॉनोमिक्स में जॉब क्रिएशन प्रक्रिया का फार्मूला भी बताया जाता है पर व्यवहार में देखें तो कोरोना संकट के दौर में कई लोगों की नौकरी चली गई व अमेरिका में तो लोग फिर से जॉब सिर्फ इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें 600 डॉलर प्रति सप्ताह का बेरोजगारी भत्ता मिलता है जो बिना काम किए घर बैठे-बैठे ही मिल रहा है तो फिर काम करने की क्या जरूरत है? इसी तरह भारत में प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों के मुफ्त खाने-पीने की व्यवस्था कर दी व नरेगा और अन्य योजनाओं के माध्यम से पैसा भी मिल रहा है तो साथ ही समाजसेवी भी अपना योगदान दे रहे हैं इसलिए कई लोग निकट भविष्य में काम पर लौटना ही नहीं चाह रहे हैं। इकॉनोमिक्स के नियम यह बताते हैं कि इकॉनोमी जब ग्रोथ करती है तो जॉब क्रिएशन होता है पर इन मामलों में तो लोग स्वयं ही जॉब से दूर रहना चाह रहे हैं जिसका इकॉनोमी की ग्रोथ से कोई लिंक नहीं है। इकॉनोमिक्स में सरकारों का रोल मोटे तौर पर टैक्स लेकर जनता की जरूरतों पर खर्च करना रहा है। कोरोना संकट के दौर में सरकारों द्वारा ब्याज दरें कम करके, फाईनेंशियल राहत देकर, पैसे बांटकर लोगों की मदद करने के प्रयास किए जा रहे हैं व सरकार लोगों द्वारा खर्चा कराने के लिए लिक्विडिटी का फ्लो भी बढ़ा रही है। सरकारों का टैक्स कलेक्शन घट रहा है व आगे और कम होने का अनुमान है व इसकी पूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में लोन लिया जा रहा है जो सरकारों को दबाव की स्थिति की ओर ले जा रहा है जिसमें इकॉनोमिक्स का कोई सिद्धांत काम का नहीं है।

शेयर बाजार, सोने-चांदी की बढ़त ने तो इकॉनोमिक्स के सभी सिद्धांतों को फेल कर दिया है क्योंकि किसी को भरोसा नहीं कि इस बढ़त का मुख्य कारण क्या है? यह बढ़त डिमांड बढ़ने से तो नहीं हुई यह तो सभी को पता है पर फिर इकॉनोमिक्स का कौनसा नियम यहां फिट बैठता है यह एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। स्टूडेंट, कारोबारी व समझदार लोगों से यही अपील है कि अपने चारों ओर हो रहे घटनाक्रमों को देखने व समझने में भी थोड़ा समय जरूर लगाए क्योंकि थ्योरी की जगह प्रेक्टिकल रूप में इकॉनोमिक्स को समझने का यह सबसे बेहतर समय है और हो सकता है कि भविष्य में निर्णय लेने का आधार पुरानी थ्योरी की जगह आज की प्रेक्टिकल नॉलेज से मिली सीख पर शिफ्ट हो जाए।

यह है कंपनियों के लिहाज से अब सबसे बड़ा खतरा!

नयी दिल्ली/एजेंसी। भारत में ज्यादातर कंपनियों का मानना है कि यदि कोविड-19 की नई लहर शुरू होती है, तो उनके कारोबार की निरंतरता प्रभावित होगी। इंटरनेशनल एसओएस के सर्वेक्षण 'रिटर्न टू वर्क' में 70 प्रतिशत भारतीय कंपनियों ने कहा कि यदि कोविड-19 का नया दौर शुरू होता है तो यह उनके कारोबार के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा।

लगभग 79 प्रतिशत कंपनियों ने कहा कि लॉकडाउन उपाय वर्तमान में उनके कारोबारी परिचालन की निरंतरता को प्रभावित कर रहे हैं। 21 प्रतिशत कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा नियंत्रण, 35 प्रतिशत ने घर से काम करने के पर्याप्त ढांचे के अभाव, 10 प्रतिशत ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों तथा 13 प्रतिशत ने कारोबार को जारी रखने की योजना के अभाव को इस समय की सबसे बड़ी अड़चन बताया। सर्वेक्षण में कहा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य को जोखिम अगले 12 माह में कारोबार की निरंतरता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत में 14 प्रतिशत कंपनियों ने आशंका जताई के इसका प्रभाव पड़ेगा। हाल में किए गए इस सर्वेक्षण में 1,000 से अधिक पेशेवरों की राय ली गई है। इंडिया इंटरनेशनल एसओएस के मीडिया निदेशक राहुल कालिया ने कहा, ''मौजूदा महामारी के दौरान हमें न केवल खुद को संक्रमण से सुरक्षित रखना है, बल्कि इसके साथ ही कर्मचारियों और कंपनियों के समक्ष कई अन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।''

'स्टूडेंट्स पर पहले से ही काफी बोझ'

नई दिल्ली/आईएएनएस। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देशभर में 6-14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों के लिए समान विषय और पाठ्यक्रम के साथ समान शिक्षा की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि छात्र पहले से ही भारी स्कूल बैग के साथ बोझ से दबे हुए हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा, आप और अधिक किताबें जोड़कर उनके बोझ को क्यों बढ़ाना चाहते हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने तर्क दिया कि आईसीएसई और सीबीएसई को मिलाकर 'वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड' किया जाना चाहिए।

तीन मोर्चों पर जूझ रहे हैं अशोक गहलोत

कैलाश शर्मा

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय एक साथ तीन मोर्चों पर जूझ रहे हैं और यह उन्हीं की कुशलता है कि तीनों मामलों में अपनी स्थिति बेहतर की हुई है। पहला है राजनीतिक मोर्चा जिसमें राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एवं उनके सहयोगी विधायकों द्वारा अचानक उठाया गया एक कदम और अब अदालत में कांग्रेस को लपेटने की चेष्टा है। दूसरा है कोरोनावायरस जनित हालात और प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना और तीसरा है राज्य सरकार की अपनी आर्थिक सेहत, जो कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान आय घटने से कदाचित प्रभावित हुई है।

चर्चा राजनीतिक परिदृश्य की। भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर देखें तो अशोक गहलोत वहां कई मायनों में सर्वोच्च स्तर पर स्थापित हैं, यूं राजनीतिक विश्लेषक प्रधानमंत्री के पद को सर्वोच्च स्तर मान लेते हैं, लेकिन कई बार प्रधानमंत्री की विफलता के कारण किसी अन्य राजनेता को सर्वोच्च स्तर स्वयमेव मिल जाता है और यह इस समय अशोक गहलोत के पास है। इसके पीछे वजह है कोरोना सरीखे संक्रमण से निपटने के लिए पहल अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में पहले की। होली के तत्काल बाद विधानसभा सत्र था, उसका विधायी कार्य-त्वरित गति से निपटाया और 13 मार्च को ही जिला कलेक्टरों की बैठक लेकर कोरोना-संक्रमण से बचाव की एडवाईजरी भी जारी कर दी। इतना ही नहीं राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पर सबसे पहले धारा 144 लगाई और जहां संक्रमण फैला वहां सबसे पहले कर्फ्यू भी। लाक डाउन की शुरुआत भी यहीं से हुई। फिर कोरोना से निपटने के जो उपाय हुए, प्रयास हुए, उन्हीं की बदौलत राजस्थान में 20 हजार से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। यह बड़ी उपलब्धि है।

बात राजनीतिक परिदृश्य की हो रही थी, तो पहले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बाहरी संक्रमण से बचाया और अब राज्य सरकार को संक्रमण से बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनका अलर्ट-रहना और तत्काल कदम उठाना इस लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हुआ। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अभी जो हालात हैं उसमें सचिन पायलट का भविष्य क्या लग रहा है। यूं इस बारे में अधिकारिक तौर पर फैसला कांग्रेस आलाकमान अर्थात सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिल कर करेंगे। पर सचिन पायलट ने जो मुश्किल राजस्थान में कांग्रेस और कांग्रेस सरकार के सामने खड़ी की है, वह वस्तुत: चिंता की बात है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में संगठन का जिम्मा उनके पास है, उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार का भार भी उनके पास है। पर अपनी दोनों जिम्मेदारियों का निर्वहन वे समुचित तरह से नहीं कर पाये, इस बात के अनेक प्रमाण हैं। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए तरह-तरह के उपक्रम करते रहे और कांग्रेस व प्रदेश सरकार को परेशानी में डालते रहे। हालांकि उन्हें पद मुक्त कर दिया गया है, फिर भी कांग्रेस को उन्होंने जिस तरह से अदालत में घसीटा है, वह राजस्थान के कांग्रेसजनों को नहीं पच रहा। अधिसंख्य कांग्रेसजनों की राय तो यही है कि सचिन पायलट अपनी इमेज खराब कर चुके हैं और उनका साथ जिन्होंने दिया उनका राजनीतिक भविष्य क्या होता है यह देखने वाली बात है। पर अशोक गहलोत ने विपरीत परिस्थितियों से जूझने की जो क्षमता प्रमाणित की है, वह कम बात नहीं है। अपने ही दल के लोगों द्वारा कोरोना-आपदा सरीखे संकट के दौर में नया राजनीतिक संकट पैदा करना बहुत खतरनाक परिदृश्य है, उस परिदृश्य से जूझना केवल अशोक गहलोत एवं उनकी टीम के वश की बात ही थी और उन्होंने इसमें अपने आप को प्रमाणित भी कर दिया है।

लॉकडाउन के दौरान 5 शहरों में 54 % घटी जहरीली हवा

नई दिल्ली/आईएएनएस। कोविड -19 के कारण लागू लॉकडाउन ने पांच भारतीय शहरों चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में खतरनाक वायु प्रदूषकों को करीब 54 प्रतिशत तक कम कर दिया है। इससे एक भारतीय मूल के शोधकर्ता के नेतृत्व वाली ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की टीम ने पाया है कि वायु में प्रदूषकों के घटने से 630 लोग समय से पहले मौत का निवाला बनने से बच गए हैं। भारत में मार्च 2020 के अंत से लागू लॉकडाउन व सामाजिक आइसोलेशन से करीब 130 करोड़ आबादी की जिंदगी प्रभावित हुई है। ब्रिटेन में सरे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर व शोधकर्ता प्रशांत कुमार ने कहा, कोविड -19 का दुनिया भर के अरबों लोगों के जीवन और आजीविका पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। कुमार ने आगे कहा, वहीं इस दुखद वैश्विक घटना ने हमें उन मानव गतिविधियों के प्रभाव की मात्रा को निर्धारित करने का मौका दिया है, जिसने हमारे पर्यावरण पर और विशेष रूप से हमारी वायु गुणवत्ता को प्रभावित किया है। सस्टेनेबल सिटीज एंड सोसाइटी जर्नल में प्रकाशित शोध में टीम ने लॉकडाउन की शुरुआत से पांच भारतीय शहरों में वाहनों और अन्य गैर-वाहन स्रोतों से उत्पन्न हानिकारक महीन कण पदार्थ (पीएम2.5) के स्तरों का अध्ययन किया। शोध में उन्होंने 11 मई, 2020 तक की अवधि पर गौर किया। टीम ने पीएम 2.5 के वितरण का विश्लेषण किया। वहीं शोध टीम ने अपने काम में इन लॉकडाउन वायु प्रदूषण के आंकड़ों की तुलना पिछले पांच वर्षों की समान अवधि से की। अंत में परिणामों से पता चला कि लॉकडाउन ने सभी पांच शहरों में हानिकारक कणों की संख्या को कम कर दिया, जिसमें मुंबई में 10 प्रतिशत तक की कमी देखी गई और दिल्ली में 54 प्रतिशत तक की कमी हुई।